मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

यूनिवर्सिटी की आड़ में भी धार्मिक ध्रुवीकरण 3
कश्मीर में होश से काम का वक्त! 4
कमीशन खोरी पर सजा नहीं 5
ठिठुरता हुआ गणतंत्र 6
अनीता यादव : तोड़फोड़ किसके इशारे पर? 8

वर्ष 34 अंक -14 फ़रीदाबाद 17-23 फ़रवरी 2019 फोन - 9999595632 ₹ 2.50

कामधेनु फंड भी गौ-रक्षक ही गटक जायेंगे

फरीदाबाद (म. मो.) गाय 'माता' है, और केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट में 'माता' के लिए कामधेनु फण्ड भी पेश कर दिया। पर ये सब फण्ड क्या गाय खुद अपने हाथ में नोट दबाये दुकान पर चारा माँगने जाएगी? नहीं, बल्कि मां के लाल सारे पैसे की सानी बना कर गटक जाएंगे और मां को भूखों मरने के लिए सड़कों पर या गौशालाओं में छोड़ देंगे।

माता की क्या दशा कर डाली है उसके राजनीतिक पूतों ने, उसे जानने के लिए फरीदाबाद के पृथला विधानसभा क्षेत्र के छांयसा गाँव की गौशाला का दौरा कर लेना काफी होगा।

छांयसा में दिल्ली पिंजरा पोल सोसाइटी जो नजफगढ़ में पंजीकृत है, की गौशाला है। इस गौशाला में इस शुक्रवार 25 गायों की लाशें एक गड्ढे में तैरती मिलीं। गाँव के लोग गौ माताओं की ऐसी दुर्दशा से बहुत नाराज हैं और प्रशासन से गौशाला संचालकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।

गायों की लाश को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मरने के बाद इनको दफनाने की जगह सीधे गड्ढे में फेंक दिया गया था और अब बारिश हो जाने से गड्ढा पानी से भर गया और इसके चलते गौशाला के कपूतों की करतूत का पता चला, जब गायों की लाशें पानी में तैरती मिलीं।

उपरोक्त दिल्ली पिंजरा पोल सोसाइटी की वेबसाइट पर उपलब्ध दो टेलीफोन नम्बरों में से एक सेवा में नहीं है जबकि दूसरा धर्मेन्द्र नामक व्यक्ति का है। धर्मेन्द्र ने फोन पर बताया कि दिल्ली पिंजरा पोल नामक संस्था से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। थोड़ा गहराई से बात करने पर धर्मेन्द्र ने माना कि उनके दादा बालकिशन प्रधान पहले गौशाला में काम करते थे पर अब वे बीमार हैं, हमारा इस गौशाला से कोई सम्बन्ध नहीं।

दादा गौशाला में क्या काम करते थे? इस सवाल पर धर्मेन्द्र पहले तो टालते रहे पर अकस्मात मुह से निकल गया कि बस चंद्रा इकठ्ठा करते थे। फिर लीपापोती करते हुए बोले कि हमारी गौशाला नजफगढ़ में है और छांयसा से कोई सम्बन्ध नहीं, यहाँ तक कि वेबसाइट पर मेरा नंबर किसी ने गलत तरीके से दिया हुआ है।

धर्मेन्द्र की बातों से जाहिर हो रहा था कि पुख्ता जवाब के अभाव में वह बातें घुमा रहे हैं। पर असल जवाब उनके मुंह से निकला ही और सच्चाई भी वही है कि गाय सिर्फ पैसा बटोरने का साधन मात्र है।

जानकार बताते हैं कि छांयसा गोशाला के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है जिसे ठेके पर देकर मोटी कमाई की जा रही है।

यहाँ बड़ा सवाल ये है कि इतनी भारी संख्या में गायों की मृत्यु कैसे हुई? फरीदाबाद में हरियाणा सरकार के मंत्री विपुल गोयल और केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी रहते हैं। विपुल गोयल गायों के नाम पर सत्संगों में संतों की सेवा के सिवाय और कुछ करते भी नहीं आज-कल। वहीं गुर्जर कैंची लिए बस फीते काट रहे हैं। तो क्या अब इन कपूतों को सामूहिक रूप से फेंकी गई माताओं की लाश पर कार्यवाही करते देखा जाएगा? या वे पूर्ववत ढोंग में लगे रहेंगे?

स्वयं मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर गौवंश प्रतियोगिता कराते नहीं अघाते। मुख्यमंत्री के दौरों में गौवंश प्रतियोगिताओं की भरमार रहती है। पर प्रतियोगिता के बाद गौशाला की गायों का क्या होता है, इस पर खट्टर का कहीं कोई ध्यान नहीं। सड़क पर फिरते गौवंश का काफिला इंसानों की जान ले रहा है और गौशालाओं में पैसा बटोरने के लिए रखी गयी गायों की जान इंसान ले रहे हैं। इस प्रकार हिसाब बराबर हो रहा है शायद।

इतनी बड़ी तादाद में गायों का गौशालाओं में मरना कोई पहली बार नहीं है। भाजपा की राजस्थान सरकार, मध्यप्रदेश सरकार और योगी के उत्तर प्रदेश की गौशालाओं में पहले भी बड़ी संख्या में गायें चारे के अभाव में मर चुकी हैं।

गाय पर राजनीति करने वाले आरएसएस और भाजपा वालों ने गौ रक्षा के नाम पर कई इंसानों की जान ले ली है पर क्या सच में ये सब गाय के लिए किया जा रहा है? यदि ऐसा होता तो आज गड्ढों में गाय की लाशें न होती। गाय के नाम पर दनादन गौशालाओं की बाढ़ सी आ गई है और खास बात ये है कि ये सारी बाढ़ भाजपा शासित क्षेत्रों में ही आई हुई है। गौशाला की आड़ में सरकारी पैसा डकारा जा रहा है और गाय भूखों मरने को मजबूर है। हाँ गाय के नाम पर उन्माद फैलाने का रास्ता जरूर खुला रखा जा रहा है।

फरीदाबाद को मोदी से मैडिकल कॉलेज की 'सौगात' के पांखड से कौन सा ऐतिहासिक कार्य किया मंत्री गूजर ने!

झूठ के पकौड़े तलना कोई इनसे सीखे

फरीदाबाद (म. मो.) चला-चली की बेला में पीएम नरेन्द्र मोदी ने कुरुक्षेत्र की जनसभा में एक साथ झज्जर के कैंसर अस्पताल व पंचकूला के एक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ-साथ एक बटन फरीदाबाद के मैडिकल कॉलेज का भी दबा दिया। स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने इस काम को फरीदाबाद के लिए एक ऐतिहासिक सौगात की संज्ञा दे डाली। बीते पांच साल से चल रहे इस कॉलेज एवं अस्पताल की मोदी द्वारा दी गयी सौगात बताकर गूजर ने भी ऐतिहासिक काम ही किया है। वैसे भी मोदी हों या कोई अन्य संघी-भाजपाई, ये लोग बिना ऐतिहासिक तो कोई काम करते ही नहीं। इनका हर पांखड ऐतिहासिक ही होता है।

सुधी पाठक बखूबी जानते हैं कि 27 फरवरी 2009 को इस ईएसआईसी अस्पताल एवं मैडिकल कॉलेज का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने किया था। इस प्रोजेक्ट को फरीदाबाद लाने में तत्कालीन विधायक एवं मंत्री ए.सी. चौधरी व तत्कालीन केन्द्रीय श्रम मंत्री ऑस्कर फर्नांडीज का बड़ा योगदान था। परन्तु देश का दुर्भाग्य यह है कि उक्त तमाम निकम्मे नेताओं से यह प्रोजेक्ट उनके शासनकाल में पूरा नहीं हो सका।

इसमें सरकार की फूटी कोड़ी भी खर्च नहीं होती। इस पर लगने वाला सारा पैसा करीब 800 करोड़ मजदूरों के वेतन से वसूला हुआ है। जिन राजनेताओं में दम था उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में बीमाकृत मजदूर न होते हुए भी मजदूरों के पैसे से इससे भी बड़े-बड़े मैडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनवाकर खड़े कर लिये। बेशक वे चले नहीं परन्तु मजदूरों के पैसे से अपने अपने क्षेत्रों का विकास तो करा ही लिया।

सन् 2009 से 2014 के 5 साल में यह कॉलेज कोई आसानी से नहीं बन गया था। ईएसआईसी के शीर्ष पर बैठे हरामखोर अफसरों व निकम्मे राजनेताओं के चलते इस प्रोजैक्ट को रद्द करने के पुरजोर प्रयास किये गये। पूरी बिल्डिंग बन जाने के बाद इसे पीपीपी (पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप) मोड से चलाने का प्रयास असफल होने के बाद हरियाणा सरकार को बिल्कुल मुफ्त देने का प्रस्ताव भी रखा गया परन्तु हरियाणा सरकार द्वारा साफ इंकार के बाद ईएसआई कार्पोरेशन ने इसे मरे हुए सांप की तरह गले में लटकाये रखा। सन् 2012 में इस अस्पताल में पैरा मैडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गये। करीब 17000 लोगों ने बैंक ड्राफ्ट के साथ आवेदन किये लेकिन एक साल बाद वह भर्ती ही रद्द कर दी गयी और आवेदकों का करोड़ों रुपया कार्पोरेशन डकार गया।

मैडिकल कॉलेज बनने से पूर्व इसी जगह पर चल रहे 200 बैड के अस्पताल को हरियाणा सरकार रो-पीट कर मात्र 17 डाक्टरों के सहारे चलाने का ड्रामा कर रही थी। न ही यहां आवश्यक चिकित्सा उपकरण थे न अन्य साजों-सामान, एक्स-रे मशीन तक भी कंडम पड़ी थी और अल्ट्रा साऊंड तक के लिये मरीजों को चार-चार माह की तारीख दी जाती थी। जाहिर है ऐसे में 200 बैड के अस्पताल में भर्ती होकर मरने का जोखिम उठाने को बमुश्किल 20-30 लोग ही आते थे।

इसके बावजूद इस अस्पताल को ईएसआई कार्पोरेशन के हवाले करने में बहुत नाटक हुए। कभी कार्पोरेशन इस काम को लटका देता था तो कभी हरियाणा सरकार। करीब दो वर्षों तक यह अस्पताल लावारिस हालत में चलता रहा। फरवरी 2013 में तत्कालीन श्रममंत्री हरियाणा शिवचरण लाल शर्मा ने इसे कार्पोरेशन के हवाले करने का 'एहसान' किया। अपने हाथ में लेने के बाद भी करीब दो साल तक कार्पोरेशन ने भी इसकी दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

करीब 700 करोड़ की नई बिल्डिंग तैयार हो जाने के बावजूद दो वर्षो तक कार्पोरेशन ने न तो डाक्टरों व स्टाफ की पर्याप्त भर्ती करी और न ही आवश्यक सामान की खरीददारी करी। कॉलेज चलाने के लिये आवश्यक एमसीआई (मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) की औपचारिकातयें पूरी करने से अधिकारी गुरेज करते रहे। उनका पूरा प्रयास रहा कि कॉलेज न चल पाये।

2011 में कॉलेज के डीन नियुक्त हो चुके डा. असीम दास इस बीच भरसक प्रयास करते रहे कि किसी तरह से एमबीबीएस छात्रों का पहला बैच शुरु हो पाये। लेकिन विरोधी शक्तियां हमेशा भारी पड़ती रही। वे एमसीआई की औपचारिकतायें पूरी ही नहीं होने देते थे। वर्ष 2015 में दीपक कुमार जब कार्पोरेशन के डीजी बने तो उन्होंने तमाम विरोधियों को ठिकाने लगाते हुए तुर्त फुर्त एमसीआई की औपचारिकतायें पूरी करके कॉलेज का पहला सत्र चालू कराया।

इस पूरे तमाशे के दौरान किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने कभी भी कोई रुचि लेने की आवश्यकता नहीं समझी। हाँ कुछ मजदूर नेता एवं नागरिकों ने जरूर इस अस्पताल के गेट पर धरने प्रदर्शन किये, 'मजदूर मोर्चा' ने अपने ढंग से इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया। हां, जुलाई 2015 में स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल ने जरूर थोड़ा सा सहयोग दिया था। डीन तथा डा. जसवंत सिंह के आग्रह पर वे उनको लेकर तत्कालीन केन्द्रीय श्रममंत्री से जरूर मिलने गये थे।

उस मुलाकात के वक्त वहां मौजूद केन्द्रीय अतिरिक्त श्रम सचिव दीपक कुमार भी मौजूद थे जो 15-20 दिन बाद ही डीजी के पद पर नियुक्त हो गये थे। लिहाजा उन्होंने पदभार संभालते ही पहली प्राथमिकता देते हुए इस कॉलेज का पहला सत्र सितम्बर 2015 में शुरू कर दिया जबकि कार्पोरेशन मुख्यालय में बैठे तमाम हरामखोर अधिकारियों ने इसे रोकने का भरसक प्रयास किया था।

शेष पेज तीन पर